राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 4413/2017

1. ज्ञान बहादुर छेत्री पुत्र श्री हीरा बहादुर, पदस्थापन-3 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन, सी/ओ 56 एपीओ।

2. दीपक सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, पदस्थापन 524 सहायक बटालियन, सी/ओ 56 एपीओ----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ, नई दिल्ली।
2. थल सेनाध्यक्ष, सेना मुख्यालय, सेना भवन, नई दिल्ली।
3. जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 24 इन्फैंट्री ब्रिगेड, सी/ओ 56 एपीओ।
4. कमांडिंग ऑफिसर, 3 मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन, सी/ओ 56 एपीओ।
5. कमांडिंग ऑफिसर, 524 एएससी बटालियन, सी/ओ 56 एपीओ----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री के.के. शाह
प्रतिवादी(ओं) के लिए:- श्री मुकेश राजपुरोहित, उप एसजी ए/डब्ल्यू
श्री उत्तम सिंह राजपुरोहित
श्री गोविंद चंडीरामनी, कैप्टन (ओआईएल) कानूनी), सेना।

माननीय जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी

निर्णय

रिपोर्ट योग्य:-

29/01/2024 को आरक्षित

09/02/2024 को निर्णय किया गया

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका को निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए प्राथमिकता दी गई हैः "इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को कृपया लागत के साथ अनुमति दी जाए और एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करके आक्षेपित कारण बताएँ नोटिस की तारीख 31.03.2017 (अनुलग्नक 7)को कृपया रद्द किया जा सकता है और अलग किया जा सकता है। यह आगे प्रार्थना की जाती है कि संशोधन के बाद जी. सी. एम. द्वारा दिए गए निष्कर्ष और सजा को कृपया पुष्टि के रूप में माने जाने का निर्देश दिया जाए। कोई अन्य आदेश भी पारित किया जा सकता है जो याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है।"

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस अदालत के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को बीकानेर में स्थित सेना इकाइयों में तैनात किए जाने के दौरान, उनके खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) की कार्यवाही प्रतिवादी no.3-जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा आदेश 26.05.2016 के माध्यम से शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दो आरोपों का आरोप लगाते हुए 19.05.2016 दिनांकित आरोप पत्र याचिकाकर्ताओं को दिया गया था; पहला आरोप आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ सेना अधिनियम, 1950 की धारा 69 (इसके बाद '1950 के अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत था, और दूसरा आरोप आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ 1950 के अधिनियम की धारा 63 के तहत था।

2. 1. इसके बाद, जी. सी. एम. की कार्यवाही 13.06.2016 को शुरू की गई और 02.11.2016 तक जारी रही; कार्यवाही पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ताओं को पहले आरोप के लिए 'दोषी नहीं' पाया गया, जबकि दूसरे आरोप के लिए 'दोषी पाया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और 7 दिनों की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. 2. इसके बाद, उपरोक्त निष्कर्ष और सजा देने के निष्कर्ष को पुष्टि के लिए पुष्टि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त प्राधिकरण ने जी. सी. एम. की कार्यवाही के अनुसार दिए गए पहले आरोप और सजा के संबंध में निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की। उक्त आदेश के बाद, जी. सी. एम. ने 24.12.2016 को फिर से बैठक की, और उसके बाद, कार्यवाही के समापन पर, 13.01.2017 का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को फिर से पहले आरोप में 'दोषी नहीं पाया गया', लेकिन दूसरे आरोप के संबंध में दी गई सजा को 7 दिन के कठोर कारावास से बढ़ाकर 2 महीने और 29

दिन के कठोर कारावास कर दिया गया, और सजा की घोषणा 16.01.2017 को की गई।

2.3. इसके बाद, उपरोक्त निष्कर्ष और बढ़ी हुई सजा को पुष्टि के लिए भेजा गया और दिनांक 08.03.2017 के आदेश के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई; पुष्टि के बाद, सजा घोषित की गई और उसके बाद उद्धरण बीकानेर में याचिकाकर्ताओं की इकाइयों द्वारा क्रमशः 27.03.2017 और 18.03.2017 को लिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं को सेवाओं से बर्खास्त करने के लिए सेना नियम 1954 (इसके बाद '1954 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 17 के साथ पठित 1950 के अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत दिनांक 31.03.2017 का आक्षेपित कारण बताएँ नोटिस जारी किया।

2.4. तत्काल याचिका दायर करने के बाद, जिसमें 31.03.2017 के कारण बताए जाने के नोटिस को चुनौती दी गई थी, प्रत्यर्थियों ने 31.07.2021 को एक और कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुलग्नक-8 के रूप में दर्ज करने की मांग की गई थी।

2.5. इस प्रकार, मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता अब उपरोक्त उद्धृत राहतों का दावा करते हुए दिनांकित 31.03.2017 और 31.07.2021 के उपरोक्त कारण बताओ नोटिसों को चुनौती दे रहे हैं।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं पर पहले से ही उपरोक्त आरोपों के लिए कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान मुकदमा चलाया गया था, और उन्हें पहले आरोप के लिए 'दोषी नहीं' पाया गया था, लेकिन दूसरे आरोप के लिए 'दोषी' पाया गया था; अब, बाद में आक्षेपित कारण बताएँ नोटिस दिनांक 31.07.2021,याचिकाकर्ताओं को दोहरे खतरे के अधीन करने के अलावा और कुछ नहीं है, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।

3. 1. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि कार्यवाही की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी और दोनों याचिकाकर्ताओं को सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में आक्षेपित कारण बताएँ नोटिस दिनांक 31.07.2021 से पता चलता है कि पहले आरोप के संबंध में कार्यवाही के निष्कर्ष की पुष्टि संबंधित प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 1950 के अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, पुष्टि प्राधिकरण कार्यवाही को संशोधन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन उसके बाद, उसके पास जीसीएम द्वारा दिए गए निष्कर्ष और सजा की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

3. 2. विद्वान वकील ने आगे कहा कि 1950 के अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, जी. सी. एम. द्वारा दी गई सजा तब तक वैध नहीं है जब तक कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, और यदि उक्त प्राधिकरण जी. सी. एम. द्वारा दिए गए निष्कर्ष और सजा से सहमत नहीं है, तो वह पुनरीक्षण के लिए कार्यवाही को नए सिरे से विचार के लिए जी. सी. एम. को वापस भेज सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान मामले में, पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया था और फिर पुष्टि करने वाले प्राधिकरण के पास उक्त आदेश की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए, प्रत्यर्थियों की आक्षेपित कार्रवाई कानून में उचित नहीं है।

3.3. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को पहले आरोप के लिए 'दोषी नहीं' माना गया था, और पांच महीने से अधिक समय के बाद, पुष्टि करने वाला प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को उसी आरोप के लिए 'दोषी' घोषित करने पर आमादा है, जो कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है, दूसरों के बीच, दोगुना खतरे के बराबर है। 3. 4. इस तरह की प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः-ए) भारत संघ और अन्य बनाम हरजीत सिंह संधू (2001) 5 एस. सी. सी. 593; बी) माइनर मार्वल जेली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका नं. 1995 के 37710 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 05.09.2001) पर निर्णय लिया।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 लागू होने के बाद, याचिकाकर्ताओं के लिए आक्षेपित कारण दर्शाओ नोटिस को चुनौती देने का उचित उपाय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) के समक्ष है।

4. 1. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त दोनों अपराध बीकानेर सैन्य स्टेशन पर एक स्कूल बस के क्रमशः सहचालक और चालक के कर्तव्यों का पालन करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पहले आरोप के 'दोषी नहीं' होने का निष्कर्ष उचित नहीं था क्योंकि उक्त आरोप जघन्य प्रकृति के अपराध से संबंधित था, और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को सेवा में बनाए रखना अवांछनीय था। इसलिए, 1950 के अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत एक प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा, दिनांकित 31.03.2017 का आक्षेपित कारण बताएँ नोटिस कानूनी रूप से उचित था।

4.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 1954 के नियमों के नियम 70 के अनुसार, पुष्टि प्राधिकरण के पास जी. सी. एम. के निष्कर्षों की पुष्टि करने के साथ-साथ गैर-पुष्टि करने का विकल्प है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के पास 1950 के अधिनियम की धारा 160 के तहत प्रदान किए गए संशोधन के लिए कार्यवाही भेजने का भी विकल्प है, और उक्त विकल्प को सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल एक बार हटाया जा सकता है।

4. 3. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पुष्टि प्राधिकरण ने 1954 के नियमों के नियम 70 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल दूसरे आरोप पर निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की, और पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, और इसलिए, पहले आरोप के संबंध में निष्कर्ष और सजा की पुष्टि नहीं की गई थी और यह 1950 के अधिनियम की धारा 153 के संदर्भ में अमान्य था।

4. 4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि सेना अधिनियम और नियमों की योजना यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि एक अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बर्खास्तगी या सेवा से हटाने की कार्रवाई, 1954 के नियमों के नियम 17 के साथ पठित 1950 के अधिनियम की धारा 20 के तहत एक प्रशासनिक कार्रवाई है, और इसलिए, प्रत्यर्थियों की आक्षेपित कार्रवाई कानून में उचित है।

4. 5. इस तरह की प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः -

क) भारत संघ और अन्य बनाम हरजीत सिंह संधू (2001) 5 एस. सी. सी. 593;

(बी) संजय मरुतिराव पाटिल बनाम भारत संघ और अन्य। (2020) 13 एस. सी. सी. 474;

(सी) सेनाध्यक्ष और अन्य बनाम मेजर धरम पाल कुकरेटी (1985) 2 एससीसी 412;

5. जवाबी दलीलों में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में ए. एफ. टी., जयपुर कार्यात्मक नहीं है, क्योंकि कोई सदस्य तैनात नहीं हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कभी-कभी सदस्य महीने में 5 दिनों के लिए अस्थायी कर्तव्य पर आते हैं और वे जुलाई, 2016 से न्यायाधिकरण की जोधपुर पीठ में नहीं बैठे हैं, और इसलिए, ए. एफ. टी. के कामकाज के अभाव में, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को उपचारहीन नहीं बनाया जा सकता है।

5. 1. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक बार जी. सी. एम. द्वारा संशोधन हो जाने और नए निष्कर्ष/सजा पारित हो जाने के बाद, इसकी फिर से समीक्षा नहीं की जा सकती है और पुष्टि करने वाले प्राधिकरण को इसकी पुष्टि करनी होगी, और यदि पुष्टि करने वाला प्राधिकरण संशोधन के बाद उक्त निष्कर्ष/सजा की पुष्टि नहीं करना चाहता है, तो वह आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च प्राधिकरण को कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

7. इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ताओं को बीकानेर में स्थित सेना इकाइयों में तैनात किए जाने के दौरान विचाराधीन कार्यवाही का सामना करना पड़ा, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर उपरोक्त आरोप लगाए गए। विचाराधीन कार्यवाही के पूरा होने के बाद, याचिकाकर्ताओं को पहले आरोप के लिए 'दोषी नहीं' पाया गया, जबकि दूसरे आरोप के लिए 'दोषी' पाया गया, और उन्हें उपरोक्त कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया।

7.1. इसके बाद, उपरोक्त कार्यवाहियों को पुष्टि के लिए पुष्टि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की गई थी, और उत्तरदाताओं ने दिनांक 24.12.2016 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियों को भेजा। उक्त आदेश के बाद, जी. सी. एम. ने फिर से बैठक की, और मामले पर पुनर्विचार करने पर, इस आशय का आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता पहले आरोप के लिए दोषी नहीं पाए गए, बल्कि दूसरे आरोप के लिए दोषी पाए गए और बढ़ी हुई सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इसके बाद, उपरोक्त सजा को पुष्टि के लिए भेजा गया और केवल दूसरे आरोप के संबंध में इसकी पुष्टि की गई। तत्पश्चात, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 31.03.2017 का आक्षेपित कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें याचिकाकर्ताओं से प्रश्नगत आरोप के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया और कहा गया कि पहले आरोप के आधार पर उनकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाता है।

8. यह न्यायालय आगे देखता है कि जैसा कि दिनांकित 19.05.2016 के आरोप पत्र से पता चलता है, याचिकाकर्ता दो आरोपों का सामना कर रहे थे और उक्त आरोपों के संबंध में जीसीएम शुरू किया गया था। उक्त आरोपों को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

प्रथम आरोप सेना अधिनियम की धारा 69: जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है, जिसे एक नागरिक अपराध के रूप में माना जाता है, यह यौन अपराध अधिनियम, 2012 से बच्चों की सुरक्षा की धारा 10 के विपरीत है, जिसमें उन्होंने 30 सितंबर 2015 को बीकानेर सैन्य स्टेशन में यौन इरादे से हवलदार ए. बी. सी. की 3 साल और 5 महीने की बेटी मिस एक्स. वाई. जेड. के जननांगों को छुआ और इस तरह एक गंभीर यौन हमला किया।

दूसरा आरोप सेना अधिनियम की धारा 63: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है और अच्छी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली चूक सैन्य अनुशासन, इसमें कि वे, 30 सितंबर 2015 को बीकानेर सैन्य स्टेशन में, यह जानने के बाद कि लगभग 03 वर्ष और 05 महीने की आयु की मिस एक्सवाईजेड को स्कूल बस में छोड़ दिया गया था, स्कूल अधिकारियों और बच्चे के माता-पिता को इसकी सूचना दिये बिना अनुचित रूप से छोड़ दिया गया था।

9. इस मोड़ पर, संजय मरुतिराव पाटिल (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना उचित माना जाता है-

9.1" शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को सेना नियमों के नियम 17 के साथ पठित सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कमांडर, प्रतिवादी 3 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि जैसा कि पहले उसे कदाचार के आरोपों के लिए समरी कोर्ट मार्शल के अधीन किया गया था, जिसके लिए बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था और इससे पहले समरी कोर्ट मार्शल ने रैंक में कमी का आदेश पारित किया था, सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी 3 द्वारा बर्खास्तगी का बाद का आदेश कानून में बुरा है और यह दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

9. 2. दूसरी ओर, विभाग की ओर से यह मामला है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत बर्खास्तगी की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है जो सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों के पास निहित है और इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 और 71 परस्पर अनन्य हैं। विभाग की ओर से इस निवेदन पर विचार करते हुए कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है जो सेना

प्रमुख और अन्य अधिकारियों के पास निहित है, इस अदालत के फैसले को हरजीत सिंह संधू [भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू, (2001) 5 एस. सी. सी. 593:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 891] को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

9. 3. उपरोक्त टिप्पणियों और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जो प्रत्यर्थी 3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था और इसकी वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है।"

10. हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रासंगिक समय पर, उपरोक्त खामियों/आरोपों को धोखाधड़ी की प्रकृति का नहीं माना गया था और अपीलार्थी पर सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत उक्त खामियों/आरोपों के लिए समरी कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी को पद में कमी का जुर्माना लगाया गया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि समरी कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को रैंक में कम किया गया था, की पुष्टि सेना प्रमुख ने सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए की थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि समरी कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को पद में कमी का जुर्माना लगाया गया था, सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान मामले में सेना प्रमुख) द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम रूप से प्राप्त हुआ। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 24 से 27 (विशेष रूप से, पैरा 27) में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए [भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू, (2001) 5 एस. सी. सी. 593:2001 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 891], सक्षम प्राधिकारी के लिए सेना नियमों के नियम 17 के साथ पठित सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

खुला था। सेना प्रमुख के पास निहित शक्ति और सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और जिसके लिए सेना नियमों के नियम 17 के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह संधू [भारत संघ बनाम हरजीत सिंह संधू, (2001) 5 एससीसी 593:2001 एससीसी (एल एंड एस) 891] में पैरा 27 में देखे गए प्रतिबंधों के अधीन है। इसका अर्थ यह है कि केवल ऐसे मामले में जहां कोर्ट मार्शल द्वारा घोषित दोषी या दोषी नहीं होने के अंतिम फैसले की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है और उसे अंतिम रूप मिल गया है, नियम 14 के साथ पठित धारा 19 या नियम 17 के साथ पठित धारा 20 के तहत आगे बढ़ने की शक्ति प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक कोर्ट मार्शल द्वारा घोषित दोषी या दोषी नहीं होने का अंतिम निर्णय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी होने की पुष्टि उपलब्ध नहीं है, तब तक नियम 14 के साथ पठित धारा 19 या नियम 17 के साथ पठित धारा 20 के तहत आगे बढ़ने की शक्ति मौजूद है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और समरी कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश की किसी भी पुष्टि के अभाव में, जिसके द्वारा अपीलार्थी को रैंक तक कम कर दिया गया था, प्रतिवादी 3 को नियम 17 के साथ पठित धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, एकमात्र प्रक्रिया जिसका पालन करने की आवश्यकता है, वह सेना नियमों के नियम 17 के तहत होगी, अर्थात्, एक व्यक्ति जिसे बर्खास्त या सेवा से हटाने की मांग की जाती है, उसे उसके खिलाफ कार्रवाई के कारण के बारे में सूचित किया गया है और उसे लिखित रूप में कोई भी कारण बताने के लिए उचित समय दिया

गया है जो उसे अपनी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के खिलाफ आग्रह करना पड़ सकता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को ऐसा अवसर दिया गया है और इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

10.1. भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना भी उचित माना जाता है। बनाम. हरजीत सिंह संधू (सुप्रा) जैसा कि नीचे दिया गया हैः "27. धारा 127 को सेना अधिनियम में पाया जाना था जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए या बरी किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए आपराधिक अदालत द्वारा या केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन उन्हीं तथ्यों पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है। 1992 के अधिनियम 37 [सेना (संशोधन) अधिनियम, 1992] द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया था। यह विलोपन कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा को अंतिम रूप देने के विधायी इरादे का संकेत देता है, बशर्ते कि उनकी पुष्टि की जाए और रद्द नहीं किया जाए। कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा की पुष्टि करने की शक्ति और अवैध या अन्यायपूर्ण होने के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति, दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से संकेत मिलता है कि कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा की यदि कानूनी और न्यायसंगत पुष्टि की जानी है, लेकिन उन्हें अवैधता या अन्याय के आधार पर रद्द किया जा सकता है। पुष्टि करने वाले प्राधिकारी पर उनकी पुष्टि करने से पहले कार्यवाही की वैधता और न्याय्यता की जांच करने का दायित्व डाला जाता है। किसी भी कोर्ट मार्शल द्वारा पारित आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य और किसी भी कार्यवाही की नियमितता, जिससे कोर्ट मार्शल का आदेश संबंधित है, के सवाल

धारा 164 के तहत याचिका के माध्यम से उठाए जा सकते हैं। एक बार निष्कर्ष और सजा, यदि कोई हो, की पुष्टि हो जाने के बाद, कोर्ट मार्शल सैन्य न्याय प्रदान करने वाला एक विशेष न्यायाधिकरण होने के नाते, नियम 14 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रयोग करने और उसके तहत जुर्माना लगाने की अनुमति नहीं होगी यदि कोर्ट मार्शल ने धारा 71 के तहत सजा के रूप में इसे देने का विकल्प नहीं चुना है। इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति देना दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और कोर्ट-मार्शल कार्यवाही, निष्कर्ष और सजा की प्रभावशीलता का भी उल्लंघन होगा। जब तक कोर्ट मार्शल द्वारा घोषित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी होने के लिए पुष्टि किया गया दोषी या दोषी नहीं होने का अंतिम निर्णय उपलब्ध नहीं है, तब तक नियम 14 (2) के साथ पठित धारा 19 के तहत आगे बढ़ने की शक्ति मौजूद है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।

11. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/कोर्ट मार्शल कार्यवाही के समापन के बाद, 1954 के नियमों के नियम 67 के अनुसार प्रश्नगत सजा का आदेश दिया गया था और उक्त सजा की घोषणा की गई थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन किया गया था; इसके बाद उक्त निष्कर्ष और सजा पुष्टि प्राधिकरण को पुष्टि के लिए भेजी गई थी और उक्त प्राधिकरण ने 1954 के नियमों के नियम 70 के अनुसार उक्त सजा की पुष्टि की थी। उक्त नियम 67 और 70 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-"67. सजा की घोषणा और कार्यवाही पर हस्ताक्षर और संचरण। (1) दया की किसी भी सिफारिश और ऐसी किसी भी सिफारिश के कारणों के साथ सजा की घोषणा तुरंत खुली अदालत में की जाएगी। सजा की घोषणा पुष्टि के अधीन की जाएगी। 70. पुष्टि। एक सामान्य या जिला कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही प्राप्त करने पर, पुष्टि

करने वाला प्राधिकारी पुष्टि की पुष्टि या इनकार कर सकता है, या, उच्च अधिकारी के लिए पुष्टि आरक्षित कर सकता है, और पुष्टि, गैर-पुष्टि, या आरक्षण दर्ज किया जाएगा और कार्यवाही का हिस्सा होगा।

12. इस न्यायालय ने आगे कहा कि पुष्टि के समय पुष्टि करने वाला प्राधिकरण एक बार निष्कर्ष और सजा को संशोधित कर सकता है और इसे 1950 के अधिनियम की धारा 160 के तहत संशोधन के लिए भेज सकता है। यह न्यायालय यह भी मानता है कि निष्कर्ष और सजा को तब तक वैध नहीं माना जा सकता जब तक कि 1950 के अधिनियम की धारा 153 के अनुसार पुष्टि करने वाले प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। उक्त धारा 153 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः "153. जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक खोज और सजा वैध नहीं है। किसी सामान्य, जिला या समरी जनरल, कोर्ट-मार्शल का कोई भी निष्कर्ष या सजा वैध नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस अधिनियम द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। 160. खोज या वाक्य का संशोधन।

(1) न्यायालय का कोई भी निष्कर्ष या सजा, जिसके लिए पुष्टि की आवश्यकता होती है, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के आदेश द्वारा एक बार संशोधित की जा सकती है और इस तरह के संशोधन पर, न्यायालय, यदि ऐसा करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है।

(2) न्यायालय में, पुनरीक्षण पर, वही अधिकारी शामिल होंगे जो मूल निर्णय पारित होने के समय मौजूद थे, जब तक कि उनमें से कोई भी अधिकारी अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित न हो।

(3) ऐसी अपरिहार्य अनुपस्थिति के मामले में उसका कारण कार्यवाही में विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, और न्यायालय संशोधन के साथ आगे बढ़ेगा, बशर्ते कि, यदि एक सामान्य कोर्ट-मार्शल है, तो इसमें अभी भी पांच अधिकारी शामिल हैं, या, यदि एक समरी जनरल या जिला कोर्ट-मार्शल है, तो तीन अधिकारी।

13. यह न्यायालय यह भी देखता है कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को पहले आरोप के लिए दोषी नहीं पाया गया था, लेकिन दूसरे आरोप के लिए दोषी पाया गया था; पुष्टि प्राधिकरण द्वारा पारित संशोधन आदेश के बाद भी, पुष्टि प्राधिकरण ने दिनांक 08.03.2017 के आदेश के माध्यम से केवल दूसरे आरोप पर निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की, जबकि पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि यह उत्तरदाताओं की ओर से दायर उत्तर के अनुबंध आर/1 में परिलक्षित होता है। दिनांकित 08.03.2017 आदेश को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-"सामान्य कार्यालय द्वारा मिनट पर सहमति, 24 इन्फैंट्री डिवीजन 14934738W (LANCE NAIK) के सम्मान में सामान्य न्यायालय में सहमति प्राधिकरण। मैं दूसरे आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि करता हूं लेकिन न्यायालय के पहले आरोप (पुनरीक्षण पर) पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता।

2. मैं अदालत द्वारा दी गई सजा (पुनरीक्षण पर) की पुष्टि करता हूं। मार्च 2017 के आठवें दिन बीकानेर में हस्ताक्षर किए गए

एस. डी./-

(बी. एस. धनोआ)

मेजर जनरल

जनरल ऑफिसर कमांडिंग

24 इन्फैंट्री डिवीजन"

14. इस न्यायालय ने आगे कहा कि पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होने के बाद, प्रत्यर्थियों ने 1950 के अधिनियम की धारा 20 के तहत 1954 के नियमों के नियम 17 के साथ पढ़ने की शक्ति का प्रयोग किया और याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा कि उनकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाता है। यह न्यायालय यह भी देखता है कि केवल दूसरे आरोप पर निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की गई थी, जिसने अंतिमता प्राप्त की, लेकिन पहले आरोप पर निष्कर्ष की अंतिमता प्राप्त नहीं करने पर, प्रत्यर्थियों की आक्षेपित कार्रवाई कानून में उचित है।

15. इस न्यायालय ने आगे कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि यदि पुष्टि करने वाला प्राधिकरण किसी भी आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता है, चाहे वह निष्कर्ष "दोषी" का हो या "दोषी नहीं", तो 1950 के अधिनियम की धारा 20 के तहत 1954 के नियमों के नियम 17 के साथ पठित शक्तियां संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होंगी। वर्तमान मामले में, पुष्टि करने वाले प्राधिकरण ने पहले आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की और इसलिए, इस तरह की पुष्टि के अभाव में, प्रत्यर्थियों ने कानून के उपरोक्त प्रावधानों के तहत उचित रूप से आक्षेपित कारण दस्सो नोटिस जारी किया है।

16. इस न्यायालय ने आगे कहा कि एक सेना इकाई में, कर्मियों को सेना के नियमों और विनियमन का सख्ती से पालन करते हुए अच्छे आचरण और उच्च स्तर के अनुशासन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं पर बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप लगाया गया था, और उसी को देखते हुए, उचित जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही से पहले की गई आक्षेपित कार्रवाई को किसी भी कानूनी दुर्बलता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

17. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत भारत संघ और अन्य बनाम अमरजीत सिंह संधू (सुप्रा) के मामले में दिया गया निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय मरुतिराव पाटिल (सुप्रा) के मामले में और अन्य निर्णयों में विचार किया गया था, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत निर्णय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं करते हैं।

18. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में और पूर्व उद्धृत पूर्ववर्ती कानूनों के साथ-साथ वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय इसे वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

19. नतीजतन, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।